अनुशासन, समर्पण और निरंतर सीखने की भावना ही है स्थायी सफलता के वास्तविक स्तंभ: डॉ. तृप्ति

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 45 | मूल्य 05 रुपये | 29 मार्च-04 अप्रैल, 2026

देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट शुरू

केदारनाथ-बद्रीनाथ में अब श्रद्धालु बिना रोक के कर सकेंगे दर्शन

पहले देशवासियों को चेतावनी फिर सफाई

उत्तराखण्ड शासन

देवभूमि रजत उत्सव

जन-जन की सरकार 4 साल बेमिसाल

उत्तरोत्तर विकास पथ पर अग्रसर उत्तराखण्ड

❝ 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखण्ड इन दोनों ही स्तंभों को लगातार मजबूत कर रहा है। ये दशक उत्तराखण्ड का दशक है। ❞

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

❝ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड सर्वांगीण विकास की नई मिसाल बन रहा है। स्थानीय उत्पाद, बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योग एवं निवेश तथा हर मौसम पर्यटन सहित देवभूमि अपनी अलौकिक विरासत को संजोते हुए विकास के नए आयाम छू रही है। ❞

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

विकसित भारत सशक्त उत्तराखण्ड

विरासत भी, विकास भी

इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी

- केदारनाथ–हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना
- दिल्ली–देहरादून एलिवेटेड रोड निर्माण
- ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रगति पर
- टनकपुर–बागेश्वर रेल सर्वे स्वीकृत
- सौंग व जमरानी बांध परियोजना
- पर्वतीय जिलों में हेली सेवा विस्तार

- ₹3.56 लाख करोड़ निवेश समझौते
- ₹1 लाख करोड़+ ग्राउंडिंग
- अर्थव्यवस्था 26 गुना वृद्धि
- ₹1.11 लाख करोड़+ वार्षिक बजट
- खुरपिया में स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप
- हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड

अर्थव्यवस्था, निवेश एवं उद्योग

- 1 गीगावाट+ सौर ऊर्जा क्षमता
- 42,000+ सोलर रूफटॉप
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (सीमांत गांव विकास)
- महक क्रांति व मिलेट्स मिशन

हरित ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास

संस्कृति एवं विरासत का संरक्षण

- केदारनाथ–बदरीनाथ मास्टर प्लान
- मानसखण्ड मंदिर माला मिशन
- शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ
- संस्कृत ग्राम पहल
- गीता अध्ययन पाठ्यक्रम में शामिल
- दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र
- स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन (गढ़वाल–कुमाऊं)

सुशासन

- 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान
- 30,000+ युवाओं को सरकारी नौकरी
- 950+ सेवाएं ऑनलाइन (अपुर्णि सरकार पोर्टल)
- 12,000 एकड़ अतिक्रमण मुक्त
- पेंशन योजनाओं में वृद्धि एवं मासिक भुगतान

- समान नागरिक संहिता
- सशक्त भू-कानून
- सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून
- नकल विरोधी कानून
- अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण

बड़े निर्णय

संकल्प से शिखर तक

नेशनल लेवल रैंकिंग व प्रोत्साहन

- निर्यात तैयारी सूचकांक में प्रथम (छोटे राज्य)
- एसडीजी इंडेक्स में शीर्ष स्थान
- स्टार्टअप रैंकिंग में 'लीडर'
- खनन सुधारों में देश में दूसरा स्थान
- शहरी सुधारों हेतु ₹264.5 करोड़ प्रोत्साहन

30 से अधिक नीतियां

- औद्योगिक नीति, पर्यटन एवं योग नीति
- नई फिल्म नीति (50% तक सब्सिडी)
- मिलेट्स नीति, कीवी नीति (70% अनुदान)
- ड्रैगन फ्रूट प्रोत्साहन योजना
- महक क्रांति 2026-36
- महिला स्वरोजगार एवं लखपति दीदी योजना आदि

नीतिगत सुधार

प्रधानमंत्री जी के नौ आग्रह

स्थानीय लोगों से: बोली-भाषा का संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छ जल, गांव से जुड़ाव, तिबारी वाले घरों को संवारें

पर्यटकों से: प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें, वोकल फॉर लोकल, यातायात के नियम अपनाएं, तीर्थों की मर्यादा का पालन करें।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी

www.uttarainformation.gov.in | DIPR_UK | UttarakhandDIPR | UttarakhandDIPR

वर्ष 15 | अंक 45

दिव्य हिमगिरि

29 मार्च-04 अप्रैल, 2026

संपादक
डॉ. कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

संवाददाता
पूनम आर्या

विज्ञापन
सुनील सेमवाल

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*
*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

धर्मांतरण और आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश

सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला न केवल एक कानूनी व्याख्या है, बल्कि यह उस लंबे समय से चले आ रहे भ्रम पर निर्णायक विराम भी है, जो धर्मांतरण और आरक्षण के अधिकारों को लेकर समाज में व्याप्त था। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जाति का दर्जा धर्म-विशेष से जुड़ा संवैधानिक प्रावधान है, और धर्म परिवर्तन के साथ ही यह दर्जा स्वत: समाप्त हो जाता है। यह निर्णय आंध्र प्रदेश से जुड़े एक मामले में आया, जहां एक व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले संरक्षण और कानूनी लाभों का दावा किया था। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, जिसने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए यह संदेश दिया कि धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का दावा संवैधानिक रूप से असंगत है। इस फैसले की जड़ें संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में निहित हैं, जो अनुसूचित जाति की परिभाषा को हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म तक सीमित करता है। यह प्रावधान ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों में उन समुदायों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, जो इन धर्मों के भीतर सदियों से सामाजिक भेदभाव का सामना करते रहे हैं। ऐसे में, जब कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, तो वह उस विशेष सामाजिक संरचना से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है, जिसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था निर्मित की गई है। हालांकि, यह भी एक सच्चाई है कि धर्म परिवर्तन के बाद सामाजिक भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। कई मामलों में व्यक्ति अपनी पूर्व सामाजिक पहचान के कारण भेदभाव झेलता रहता है। यही वह तर्क है, जिसके आधार पर समय-समय पर यह मांग उठती रही है कि धर्मांतरण के बावजूद आरक्षण का लाभ जारी रहना चाहिए। लेकिन न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया कि संवैधानिक लाभों का निर्धारण व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि विधिक प्रावधानों के आधार पर होगा। यह फैसला केवल कानूनी स्पष्टता ही नहीं लाता, बल्कि नीति-निर्माताओं के सामने भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है- क्या वर्तमान सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप इन प्रावधानों की पुनर्समीक्षा की आवश्यकता है? यदि समाज में भेदभाव की प्रकृति बदल रही है, तो क्या कानून को भी उसके अनुरूप विकसित नहीं होना चाहिए? इसके साथ ही, यह निर्णय प्रशासनिक स्तर पर जागरूकता की कमी को भी उजागर करता है। यदि संविधान और कानून पहले से ही इस विषय पर स्पष्ट हैं, तो फिर समाज में इस तरह का भ्रम क्यों बना रहा? यह प्रश्न सरकारों और संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी तय करता है कि वे ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर स्पष्ट और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करें। अंतत:, सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला एक मजबूत संदेश देता है कि संवैधानिक व्यवस्थाएं स्पष्ट हैं और उनका पालन अनिवार्य है। हालांकि, यह बहस यहीं समाप्त नहीं होती। सामाजिक न्याय की अवधारणा निरंतर विकसित हो रही है, और ऐसे में यह आवश्यक है कि कानून, समाज और नीति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए संवाद जारी रहे।

डॉ. कुँवर राज अस्थाना

पहले देशवासियों को चेतावनी फिर सफाई

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले देशवासियों को संभावित वैश्विक संकट के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी, जिसके बाद देश में लॉकडाउन जैसी आशंकाओं को लेकर अफवाहें तेज हो गईं। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा था कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं और आने वाला समय बड़ी परीक्षा लेने वाला है, इसलिए केंद्र और राज्यों को 'टीम इंडिया' की तरह मिलकर काम करना होगा। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर संभावित प्रतिबंधों और आपूर्ति संकट को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। स्थिति स्पष्ट करने के लिए केंद्र सरकार के तीन वरिष्ठ मंत्रियों को सामने आकर कहना पड़ा कि देश में लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और ईंधन व आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर फिर दोहराया कि हालात पर नजर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर बनते अनिश्चित हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले संसद के उच्च सदन में देश को संभावित चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। राज्यसभा में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं और इसका असर ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक रह सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय देश की बड़ी परीक्षा ले सकता है, इसलिए केंद्र और राज्यों को 'टीम इंडिया' की भावना के साथ मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में जो कठिन हालात बन रहे हैं, उनसे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। उन्होंने कोरोना महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी देश ने एकजुट होकर चुनौती का सामना किया था और इस बार भी उसी तरह समन्वय की जरूरत होगी। पीएम मोदी ने राज्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि हर स्तर पर तैयारियां मजबूत रखनी होंगी ताकि किसी भी संभावित संकट का प्रभाव कम किया जा सके। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट के समय बाहरी चुनौतियों के साथ-साथ आंतरिक अव्यवस्था और अफवाहों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में कानून-व्यवस्था से जुड़ी सभी एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि तटीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और रणनीतिक ठिकानों की निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से संयम बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि संकट के समय कुछ लोग झूठी खबरें फैलाकर या जमाखोरी करके हालात का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए राज्यों और प्रशासनिक एजेंसियों को ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि शांत मन से हर चुनौती का सामना करना ही देश की ताकत है और यही पहचान भी है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ जगहों पर संभावित आपूर्ति संकट और प्रतिबंधों को लेकर अफवाहें फैलने लगीं। ईंधन की उपलब्धता, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और संभावित लॉकडाउन को लेकर लोगों में चिंता बढ़ने लगी। कई जगहों पर लोगों ने अतिरिक्त सामान खरीदने की कोशिश भी शुरू कर दी, जिससे बाजार में अनावश्यक हलचल देखी गई। इसी बीच केंद्र सरकार के तीन वरिष्ठ मंत्रियों को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। संसदीय

कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश में लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इस तरह की खबरें पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हालात पर नजर रखे हुए है और केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। रिजिजू ने चेतावनी दी कि यदि कोई कृत्रिम कमी पैदा करने या जमाखोरी की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अफवाहों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कोविड-19 जैसी स्थिति नहीं बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत ने पर्याप्त भंडार बनाए हुए हैं और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बिना वजह सामान जमा न करें और केवल जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करें। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी स्पष्ट किया कि देश में लॉकडाउन की खबरें निराधार हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति को लेकर वास्तविक समय पर निगरानी की जा रही है और ईंधन तथा एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि "तैयारी" का मतलब प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता है, न कि आम लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध। पुरी ने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित न हो और लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तीनों मंत्रियों के बयानों के बाद सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की कि हालात नियंत्रण में हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि तेल कंपनियों और राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण व्यवस्था में कोई बाधा न आए। प्रशासन को जमाखोरी रोकने और आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।

अंतरराष्ट्रीय हालात चुनौतीपूर्ण जरूर, लेकिन भारत की तैयारी मजबूत

प्रधानमंत्री के राज्यसभा संबोधन के बाद फैली चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार के मंत्रियों ने सामने आकर स्थिति स्पष्ट की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह समझ से परे है कि इस तरह की गलत खबरें कौन फैला रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की घबराहट पैदा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर हालात पर नजर रख रही हैं और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन भारत की तैयारी मजबूत है। उन्होंने कहा कि ईंधन और जरूरी वस्तुओं का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आपूर्ति श्रृंखला सामान्य रूप से काम कर रही है। उन्होंने लोगों से संयम बरतने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने बताया कि तेल और गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन लगाने जैसी कोई स्थिति नहीं है और सोशल मीडिया पर फैल रही खबरें भ्रामक हैं। सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिए कि यदि कहीं कृत्रिम कमी पैदा करने या जमाखोरी की कोशिश होती है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। राज्यों से भी कहा गया कि वे स्थानीय स्तर पर बाजारों की निगरानी करें और लोगों को भरोसा दिलाएं कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होगी।

मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी का स्पष्ट संदेश, देश में लॉकडाउन नहीं

27 मार्च, शुक्रवार शाम आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत की तैयारी मजबूत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रखना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि देश में किसी प्रकार का लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और केंद्र तथा राज्य मिलकर हालात का सामना करें। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाएं और जनता को सही जानकारी दें। बैठक में यह भी कहा गया कि कच्चे तेल की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और देश के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है। प्रशासन को निर्देश दिए गए कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आने दी जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-१९ के दौरान जिस तरह 'टीम इंडिया' की भावना से काम किया गया था, उसी तरह समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा। कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों में पहले प्रधानमंत्री की चेतावनी, फिर अफवाहों का दौर और उसके बाद सरकार की ओर से स्पष्टीकरण का सिलसिला देखने को मिला। राज्यसभा में संभावित संकट को लेकर प्रधानमंत्री के अलर्ट के बाद पैदा हुई चिंता को सरकार और मंत्रियों ने भरोसा देकर शांत करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि हालात पर नजर है, लेकिन देश में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं बनने वाली है। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इनमें आंध्र प्रदेश के एन. चंद्रबाबू नायडू, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, पंजाब के भगवंत मान, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, जम्मू-कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, झारखंड के हेमंत सोरेन, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस समेत कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में केंद्र सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित कैबिनेट सचिव और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने ऊर्जा भंडार, आपूर्ति श्रृंखला और अंतरराष्ट्रीय हालात के संभावित असर पर प्रस्तुति दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राज्यों से समन्वय के साथ काम करने और स्थानीय स्तर पर निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए।

देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट शुरू

करीब 25 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद शनिवार 28 मार्च पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर को बड़ी सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया। इसके साथ ही देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। पहले चरण में यह एयरपोर्ट सालाना करीब 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा, जबकि चारों चरण पूरे होने पर इसे एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र के किसानों, उद्योगों और युवाओं के लिए रोजगार और निवेश के नए अवसर लेकर आएगा। उन्होंने इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास का नया इंजन बताते हुए कहा कि यह परियोजना पूरे उत्तर भारत को वैश्विक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार देगी। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट

करीब ढाई दशक के लंबे इंतजार के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को बड़ी सौगात मिल गई है। जेवर की धरती से अब विकास की नई उड़ान भरनी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया। इसके साथ ही देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। यह एयरपोर्ट न केवल हवाई कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एनसीआर और आसपास के राज्यों के आर्थिक परिदृश्य को भी बदलने में बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर में एयरपोर्ट के फेज-1 का लोकार्पण किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगा और यह परियोजना किसानों, उद्योगों तथा रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगी। उन्होंने कहा एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्यशैली का उदाहरण है और इससे पूरे क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जेवर का यह एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, फरीदाबाद, पलवल, इटावा और आसपास के कई जिलों को सीधा लाभ देगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश लंबे समय से बड़े बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का इंतजार कर रहा था और अब यह क्षेत्र तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा है। यहां से दुनिया के लिए उड़ानें शुरू होंगी और यह एयरपोर्ट विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को मजबूत करेगा। जेवर एयरपोर्ट पूरे उत्तर भारत को दुनिया से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा और इससे निवेश, पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई दिशा मिलेगी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट राज्य के विकास का नया अध्याय है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उद्घाटन के दौरान एयरपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधाओं और डिजाइन की भी जानकारी दी गई।

क्षेत्रीय विकास, रोजगार और निवेश को मिलेगी नई रफ्तार

जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उत्तर भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। पहले चरण में यह एयरपोर्ट सालाना करीब 1.2 करोड़ यात्रियों को सेवा देगा। भविष्य में विस्तार के साथ इसकी क्षमता 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन सकता है। यह एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ मिलकर एक डयूल-एयरपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करेगा। इससे दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते एयर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर विकल्प मिलेंगे। साथ ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली जाने की जरूरत भी कम होगी। यहां मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब, वेयरहाउसिंग जोन, एमएसएमई क्लस्टर और इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी। कृषि क्षेत्र को भी इस एयरपोर्ट से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। किसानों की फल, सब्जी और डेयरी उत्पादों को सीधे विदेशों तक भेजने की सुविधा मिलेगी। इससे उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे और कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र को भी नई गति मिलने की संभावना है। एयरपोर्ट से जुड़े एक्सप्रेसवे और रेल कनेक्टिविटी भी विकसित की जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कनेक्शन से यह एयरपोर्ट पूरे उत्तर भारत से जुड़ जाएगा। नमो भारत ट्रेन और मेट्रो नेटवर्क से भी इसे जोड़ने की योजना है।

आधुनिक सुविधाएं, विशाल रनवे और 'नेट-जीरो' एयरपोर्ट की खास पहचान

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आधुनिक तकनीक और पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। एयरपोर्ट का आर्किटेक्चर भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। इसकी छत को यमुना, गंगा और हिंडन नदियों की लहरों जैसा डिजाइन दिया गया है। टर्मिनल के भीतर पारंपरिक जाली कार्य और लाल पत्थरों का इस्तेमाल, जो स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। एयरपोर्ट पर 3,900 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है, जो दुनिया के बड़े वाइड-बॉडी विमानों को संभालने में सक्षम है। एयरपोर्ट को 24 घंटे संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। यहां 80 एकड़ में मल्टी-मोडल कार्गो हब विकसित किया गया है। शुरुआती चरण में सालाना 2.5 लाख मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग की क्षमता रखी गई है। भविष्य में इसे और बढ़ाया जाएगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और निर्यात उद्योग को बड़ा फायदा मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 'नेट-जीरो' उत्सर्जन प्रोजेक्ट के रूप में डिजाइन किया गया है। यहां सोलर एनर्जी, वर्षा जल संचयन, ऊर्जा दक्ष भवन और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। इससे पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ेगा और यह देश का पहला बड़े पैमाने का पर्यावरण अनुकूल एयरपोर्ट माना जा रहा है।

केदारनाथ-बद्रीनाथ में अब श्रद्धालु बिना रोक के कर सकेंगे दर्शन

चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार बड़ी राहत की खबर है। उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या तय करने की व्यवस्था यानी 'कैपिंग' को समाप्त कर दिया है। अब बिना किसी संख्या सीमा के श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे और केवल लिमिट पूरी होने के कारण किसी को वापस नहीं लौटाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान आने वाले हर श्रद्धालु को सुगम और सुरक्षित दर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सरकार का कहना है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ट्रैफिक और ठहरने की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। कैपिंग हटाने के फैसले से देशभर के भक्तों में उत्साह बढ़ गया है और पर्यटन कारोबार को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

चारधाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या तय करने की व्यवस्था यानी 'कैपिंग' को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि अब किसी भी श्रद्धालु को केवल संख्या पूरी होने के कारण दर्शन से नहीं रोका जाएगा। सरकार के इस फैसले को आस्था का सम्मान और श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी जाती थी। इसके चलते कई भक्तों को घंटों इंतजार करना पड़ता था, जबकि कुछ को बिना दर्शन किए ही वापस लौटना पड़ता था। खासकर दूर-दराज राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह स्थिति भावनात्मक रूप से भी कठिन होती थी। कई श्रद्धालु महीनों पहले से तैयारी करते थे, लंबा सफर तय करते थे, लेकिन संख्या पूरी होने पर उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता था। सरकार के नए फैसले से अब ऐसे हालात नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर श्रद्धालु को भगवान के दर्शन का अवसर मिले और यात्रा को अधिक सुगम बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। केदारनाथ और बद्रीनाथ में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कैपिंग खत्म होने का फैसला श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि यह फैसला उनकी भावनाओं का सम्मान है और इससे भगवान के दर्शन की उम्मीद और मजबूत हुई है। पर्यटन और धार्मिक संगठनों ने भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। होटल, ट्रांसपोर्ट, स्थानीय व्यापार और रोजगार पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। धामी सरकार ने यात्रा से पहले तैयारियों को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया है। प्रशासन यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और ठहरने की व्यवस्थाओं को मजबूत करने में जुटा है। यात्रा मार्गों पर चिकित्सा केंद्र, एंबुलेंस, पेयजल, शौचालय और पार्किंग जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा मौसम और भीड़ प्रबंधन के लिए भी विशेष योजना बनाई जा रही है। धामी सरकार का मानना है कि चारधाम यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, पर्यटन और अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा आयोजन है। इसलिए "नो कैपिंग" नीति लागू कर श्रद्धालुओं को खुला अवसर देना सरकार की सराहनीय पहल मानी जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, जिसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस बार चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी: इस बार चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। अभी तक करीब 10 लाख के आसपास श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले साल 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की थी, ऐसे में इस बार उससे भी अधिक संख्या पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए "नो कैपिंग" नीति अपनाई गई है। राज्य सरकार ने यात्रा मार्गों पर सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ी मार्गों पर यातायात सुचारु रखने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं के लिए अस्थायी अस्पताल, डॉक्टरों की तैनाती और आपातकालीन सेवाओं को भी बढ़ाया जा रहा है। चारधाम यात्रा में कैपिंग हटाने को लेकर विपक्ष ने कुछ सवाल भी उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि बिना पूरी तैयारी के लिमिट हटाने से अव्यवस्था बढ़ सकती है। हालांकि सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि सभी विभागों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और व्यवस्थाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। धामी सरकार का संदेश साफ है कि इस बार यात्रा "खुली और सुगम" होगी। कैपिंग हटाने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने जैसे फैसलों को सरकार की बड़ी पहल माना जा रहा है। इससे पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कई लोग वर्षों से चारधाम का सपना देखते हैं और भगवान के दर्शन को जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य मानते हैं। सरकार की यह पहल आस्था को सम्मान देने के साथ यात्रा को अधिक सुगम और व्यापक बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

अनुशासन, समर्पण और निरंतर सीखने की भावना ही है स्थायी सफलता के वास्तविक स्तंभः डॉ. तृप्ति

मानव सेवा को अपना धर्म मानने वाली डॉ तृप्ति चौधरी ने अब तक कई लोगों की आंखों के सफल ऑपरेशन कर उनके चेहरे पर मुस्कान वापिस लाई है। डॉ तृप्ति से हुई लोकेश राज अस्थाना की बातचीत के प्रमुख अंश।

डॉ. तृप्ति चौधरी
MBBS, DOMS, DNB, MNAMS, FNEI (Medical Retina)
कंसल्टेंट सर्जन, शिव चिकित्सालय, देहरादून

अपनी पारिवारिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं।

मेरा जन्म पटना के एक उच्च शिक्षित परिवार में हुआ है। मैने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजेंद्र विद्यालय जमशेदपुर, झारखंड से पूर्ण की। शिक्षा के प्रति मेरी शुरू से ही गहरी लगन रही है। श्री बी0एम0 पाटिल मेडिकल कॉलेज बीजापुर से एमबीबीएस, केमपेगैडा इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलुरू से नेत्र विभाग में डिप्लोमा तथा वेनू आई इंस्टीटयूट, दिल्ली से डीएनबी की डिग्री पूर्ण की।

चिकित्सा क्षेत्र में आने के प्रेरणास्रोत्र कौन रहे है?

चिकित्सा के क्षेत्र में आने के मेरे प्रेरणास्रोत्र मेरे माता-पिता श्रीमति किरण चौधरी एवं श्री बुद्धिनाथ चौधरी रहे है। चूंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि उच्च शिक्षा से परिपूर्ण है लिहाजा मेरे परिजन चाहते थे कि मैं एक चिकित्सक के रूप में समाज की सेवा करने में अपना योगदान दूं। एक नेत्र रोग विशेषज्ञ और परफेक्शनिस्ट के रूप में मेरा मानना है कि अनुशासन, समर्पण और निरंतर सीखने की भावना ही स्थायी सफलता के वास्तविक स्तंभ है।

आपकी उपलब्धियों के बारे में बताइये।

मैने दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय हास्पिटल में इंटरनर्शिप की तथा डा0 एनसी जोशी मैमोरियल कॉलेज में एक रेसिडेंट के रूप में ढाई वर्ष कार्य किया। गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, देहरादून में 5 वर्ष ओपथालॉजी सर्जन (रेटिना स्पेशलिस्ट) के रूप में कार्य किया तथा वर्तमान में शिव चिकित्सालय देहरादून में एक सीनियर कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हूं। मेरे द्वारा अब तक अनेक मरीजों का सफल नेत्र ऑपरेशन कर उनकी नेत्र ज्योति को वापिस दिलाया गया है। इसके अलावा मैं नवजात शिशु आरओपी स्क्रीनिंग में भी पारंगत हूँ। इंडियन काउंसिल आफॅ मेडिकल रिसर्च (ICMR), नई दिल्ली द्वारा 2009 में शार्ट टर्म स्टूडेंटशिप अवार्ड 2009 से सम्मानित किया गया।

चिकित्सा के क्षेत्र में आपका कोई यादगार अनुभव।

जब मैं दिल्ली में कार्यरत थी तब एक 15 साल की लड़की, जिसकी शुगर की वजह से दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो गया था, का सफल आपरेशन किया था। आपरेशन के बाद जब उसकी आंखों की पट्टी खोली गई तो वो वह खुशी की वजह से रोने लगी जिसकी वजह से पूरे अस्पताल का माहौल भावुक हो गया था। इसके अलावा मैने अपने एक मरीज की आंखों का सफल आपरेशन किया था और इसके बाद जब उसकी नौकरी लगी तो वह मुझसे मिलने आया लेकिन उसकी वेशभूषा इतनी बदल चुकी थी कि मैं उसको पहली बार में पहचान ही नहीं पाई। इस तरह के मेरे सामने कई अवसर ऐसे आएं और तब मुझे लगा कि यदि हम अपना कार्य ईमानदारी और कुशलतापूर्वक करे तो हम लोगों के जीवन की दिशा ही बदल सकते है।

दिव्य हिमगिरी के पाठकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी?

पाठकों के लिए मेरा संदेश है कि निरंतर मेहनत एवं लगन से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते है। अशांति और तनाव के इस दौर में मैं सभी पाठकों को गीता के श्लोकों को अपने जीवन में उतारने का निवेदन करती है। हमारा जीवन इस पृथ्वी पर निर्धारित है और मानव सेवा ही परम धर्म है। इसके अलावा आंखें अनमोल है, इसका विशेष ध्यान रखें और डायबिटीज के मरीज अपनी आंखों की नियमित जांच कराएं।

जलवायु परिवर्तनः भविष्य नहीं, वर्तमान का महाविनाशकारी संकट

ललित गर्ग

आज मानव सभ्यता जिस सबसे बड़े संकट के सामने खड़ी है, वह युद्ध, महामारी या आर्थिक मंदी नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन है। दुनिया आज जलवायु संकट के ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां हर नया आंकड़ा खतरे की घंटी बनकर सामने आ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ताजा रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि 2015-2025 का दशक अब तक का सबसे गर्म दौर रहा है। यह केवल एक सांख्यिकीय तथ्य नहीं, बल्कि पृथ्वी के बदलते स्वभाव का गंभीर संकेत है। रिपोर्ट बताती है कि ग्रीनहाउस गैसों का स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है और पृथ्वी का एनर्जी इम्बैलेंस लगातार बढ़ रहा है। महासागर, जो जलवायु संतुलन के सबसे बड़े नियंत्रक माने जाते हैं, अब 90 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त गर्मी सोख रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि पृथ्वी का तापमान केवल हवा में ही नहीं, जल और भूमि के भीतर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन अब धीरे-धीरे आने वाली समस्या नहीं रही, बल्कि यह वर्तमान का संकट बन चुका है। दुनिया के अनेक हिस्सों में असामान्य गर्मी, बाढ़, सूखा, चक्रवात और जंगल की आग जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। प्रति का संतुलन बिगड़ रहा है और मौसम का मिजाज अनिश्चित होता जा रहा है। कहीं अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ रही है तो कहीं महीनों तक बारिश नहीं हो रही। यह असंतुलन सीधे-सीधे मानव जीवन, कृषि, जल संसाधनों और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इस बदलते मौसम ने सबसे ज्यादा मनुष्य के स्वास्थ्य पर हमला किया है। भारत के संदर्भ में यह संकट और भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के अनेक शहरों में तापमान 48 से 50 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि पहले 45 डिग्री को ही अत्यधिक गर्मी माना जाता था। अब असामान्य गर्मी ने फरवरी और मार्च जैसे महीनों को भी झुलसाना शुरू कर दिया है। हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ रही हैं। इसका असर केवल स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि बिजली, पानी, खेती, श्रम, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी ने केवल मानव जीवन ही नहीं, बल्कि वन्यजीव, पेड़-पौधे और सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को भी संकट में डाल दिया है। जलवायु परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ा कारण मानव का विकास मॉडल है। कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई, अनियोजित शहरीकरण, औद्योगीकरण और संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पृथ्वी को लगातार गर्म कर रहा है। आज वैश्विक तापमान लगभग एक लाख 25 हजार वर्षों के उच्चतम स्तर के आसपास पहुंच चुका है। यह स्थिति बताती है कि समस्या प्रकृति में नहीं, बल्कि मानव की जीवनशैली और विकास की दिशा में है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां इस संकट को और अधिक खतरनाक बना रही हैं। दुनिया के अनेक हिस्सों में युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं। युद्ध केवल मानव जीवन और अर्थव्यवस्था को ही नष्ट नहीं करते, बल्कि पर्यावरण को भी गहरा नुकसान पहुंचाते हैं। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक, रसायन, धातु, ईंधन और आग से वातावरण में भारी मात्रा में जहरीली गैसें फैलती हैं। तेल भंडारों में आग, रासायनिक संयंत्रों का नष्ट होना और सैन्य गतिविधियां वातावरण में कार्बन उत्सर्जन को कई गुना बढ़ा देती हैं। इस प्रकार युद्ध और जलवायु परिवर्तन मिलकर पृथ्वी को दोहरे संकट की ओर धकेल रहे हैं। भारत सहित दुनिया के लगभग 75 प्रतिशत जिले किसी न किसी जलवायु जोखिम के दायरे में आ चुके हैं। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग रहा है। दूसरी ओर समुद्र का जलस्तर बढ़ने से मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे तटीय शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। यदि समुद्र स्तर इसी गति से बढ़ता रहा तो आने वाले दशकों में तटीय आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हो सकता है। यह केवल पर्यावरण संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संकट भी बन सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में तेजी से कटौती नहीं की गई, तो तापमान के नए-नए रिकॉर्ड टूटते रहेंगे और पृथ्वी रहने योग्य स्थान कम होती जाएगी। जल संकट, खाद्य संकट, स्वास्थ्य संकट और प्रवासन जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। दुनिया के अनेक वैज्ञानिक अब चेतावनी दे रहे हैं कि यदि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित नहीं किया गया, तो पृथ्वी का पारिस्थितिक संतुलन गंभीर रूप से बिगड़ सकता है। लेकिन इस संकट में ही अवसर भी छिपा हुआ है। यह समय विकास मॉडल को बदलने का है। ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। शहरों को कंक्रीट के जंगल बनाने के बजाय हरित शहर बनाना होगा। जल प्रबंधन को जन आंदोलन बनाना होगा। वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण और नदियों के संरक्षण पर गंभीरता से काम करना होगा। कृषि को जलवायु अनुकूल बनाना होगा, कम पानी वाली फसलों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। साथ ही जिला स्तर पर हीट एक्शन प्लान,

जल संरक्षण योजना, वृक्षारोपण अभियान और स्थानीय पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम लागू करने होंगे। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई केवल सरकारें नहीं जीत सकतीं, इसके लिए समाज, उद्योग, वैज्ञानिक और आम नागरिक सभी को मिलकर काम करना होगा। दुनिया की महाशक्तियों के लिए यह समय सबसे बड़ी परीक्षा का समय है। यदि वे केवल आर्थिक विकास और सैन्य शक्ति की दौड़ में ही उलझी रहीं और पृथ्वी के भविष्य की चिंता नहीं की, तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। उन्हें यह समझना होगा कि पृथ्वी बचेगी तो अर्थव्यवस्था भी बचेगी, मानव सभ्यता भी बचेगी और विकास भी बचेगा। यदि पृथ्वी ही तपती और असंतुलित हो गई, तो सारी प्रगति बेकार हो जाएगी। आज आवश्यकता है कि दुनिया की महाशक्तियां कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कठोर और बाध्यकारी नीतियां बनाएं, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करें, वनों की कटाई रोकें और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दें। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि अनेक क्षेत्र रहने योग्य नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की चुनौती नहीं, वर्तमान का संकट है। यदि आज निर्णायक कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को एक असंतुलित और तपती हुई पृथ्वी विरासत में मिलेगी। यह तपती हुई पृथ्वी मानव जीवन के लिए विनाश का कारण भी बन सकती है। लेकिन यदि दुनिया समय रहते चेत गई, तो यही संकट एक नए, संतुलित और टिकाऊ विकास मॉडल की शुरुआत भी बन सकता है। पृथ्वी को बचाना अब विकल्प नहीं, मानव अस्तित्व की अनिवार्यता बन चुका है।

यूजेवीएन लिमिटेड को "वॉटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स" में बांध सुरक्षा सम्मान

उत्तराखंड सरकार के उपक्रम यूजेवीएन लिमिटेड को प्रतिष्ठित "वॉटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स" के अंतर्गत "सर्वश्रेष्ठ पहल-बांध सुरक्षा" श्रेणी में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण एवं संरचनात्मक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं नवाचारपूर्ण प्रयासों हेतु प्रदान किया जाता है। यूजेवीएन लिमिटेड राज्य में 1440.60 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ जलविद्युत एवं सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। निगम द्वारा ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से नई परियोजनाओं के विकास एवं निर्माण के साथ साथ पुरानी परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं सुरक्षित संचालन पर भी समान प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रबंध निदेशक अजय कुमार सिंह ने कहा कि यह सम्मान निगम के कुशल प्रबंधन, तकनीकी दक्षता तथा नवाचार से कार्मिकों के ऊर्जा उत्पादन हेतु समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यूजेवीएनएल द्वारा बांधों एवं बैराजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आधुनिक तकनीकों, नियमित निरीक्षण और प्रभावी अनुरक्षण प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है जिससे बांधों, बैराजों, शक्ति नहरों तथा अन्य संबंधित संरचनाओं की दीर्घकालिक सुरक्षा तथा स्थिरता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2015 से यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा केंद्रीय जल आयोग एवं विश्व बैंक के सहयोग से संचालित बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना में सक्रिय भागीदारी की जा रही है, जिसके अंतर्गत छह पुराने बांधों एवं बैराजों के पुनर्वास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही निगम द्वारा परिचालन एवं अनुरक्षण नियमावली तथा आपातकालीन कार्ययोजना जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी दस्तावेजों को तैयार करने का कार्य भी किया जा रहा है। प्रबंध निदेशक अजय कुमार सिंह ने महिला सशक्तिकरण को संगठन की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए कहा कि महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों को परियोजना स्थलों पर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूजेवीएन लिमिटेड भविष्य में भी सुरक्षित, विश्वसनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए बांध सुरक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करता रहेगा।

हिमालय संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी पारिस्थितिकी की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में हिमनद झीलों से उत्पन्न संभावित आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीक आधारित उपायों को अपनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार नेशनल ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम (NGRMP) के अंतर्गत राज्य की 13 संवेदनशील हिमनद झीलों की निगरानी, जोखिम आकलन एवं न्यूनीकरण हेतु एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। इस वर्किंग ग्रुप का नोडल संस्थान वाडिया इंस्टीटयूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को नामित किया गया है। उक्त वर्किंग ग्रुप में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीटयूट, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर तथा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ भू-वैज्ञानिकों को सम्मिलित किया गया है। वर्किंग ग्रुप द्वारा परियोजना के अंतर्गत आधुनिक निगरानी प्रणाली के विकास, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) की स्थापना, अनुसंधान एवं तकनीकी अध्ययन तथा जोखिम न्यूनीकरण उपायों के समन्वित क्रियान्वयन का कार्य किया जाएगा। परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुल रू0 9.00 करोड़ की धनराशि मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित की गई है। इसमें से रू0 7.80 करोड़ की धनराशि वाडिया संस्थान को उपकरणों की खरीद, सैटेलाइट इमेजरी, सॉफ्टवेयर एवं कम्प्यूटेशनल सुविधाओं के विकास, फील्ड ऑपरेशन्स तथा मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त रू0 1.20 करोड़ की धनराशि फील्ड सर्वेक्षण, जन-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा पूर्व व्यय के समायोजन हेतु उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से वाडिया संस्थान को अवमुक्त की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह परियोजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य हिमनद झीलों से उत्पन्न संभावित आपदाओं के जोखिम को न्यूनतम करना तथा समयबद्ध चेतावनी तंत्र विकसित करना है।

सीएम धामी ने पीएम मोदी को चारधाम यात्रा के लिए किया आमंत्रित

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें उत्तराखंड आने का न्योता दिया। दिल्ली में हुई इस शिष्टाचार भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी चारधाम यात्रा में शामिल होने का आग्रह भी किया। धामी ने प्रधानमंत्री को टिहरी जिले स्थित प्रसिद्ध मां सुरकंडा देवी मंदिर का स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए देवभूमि आने का निमंत्रण दिया। मुलाकात के दौरान चारधाम यात्रा की तैयारियों, पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक इंतजाम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा प्रदेश के पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को नई गति देगा। वहीं, चारधाम यात्रा से पहले इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड आने का औपचारिक न्योता दिया और आगामी चारधाम यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। मुलाकात के दौरान धामी ने प्रधानमंत्री को टिहरी जिले स्थित प्रसिद्ध मां सुरकंडा देवी मंदिर का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास, पर्यटन, अवसंरचना और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और राज्य सरकार यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक इंतजाम कर रही है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में राज्य सरकार सड़क, स्वास्थ्य, संचार, पार्किंग, आवास और आपदा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड आकर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाएं। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को राज्य में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पुनर्निर्माण परियोजनाओं सहित कई योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिला है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री का इन परियोजनाओं के लिए निरंतर सहयोग देने पर आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए तकनीक का भी व्यापक उपयोग कर रही है। इस बार पंजीकरण व्यवस्था को और सरल बनाया गया है, साथ ही यात्रियों के लिए हेल्पलाइन, कंट्रोल रूम और मेडिकल सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और आपदा प्रबंधन टीमें तैनात की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के दर्शन कराए जाएं और यात्रा का अनुभव बेहतर बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में पर्यटन के नए डेस्टिनेशन विकसित करने की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ एडवेंचर, इको और होमस्टे पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को विकसित कर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, राज्य में हेली सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को भी यात्रा में सुविधा मिल सके।

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को सुरकंडा देवी मंदिर का स्मृति चिन्ह भेंट किया

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को सुरकंडा देवी मंदिर का स्मृति चिन्ह भेंट किया। यह मंदिर टिहरी जनपद में स्थित एक प्रमुख शक्ति पीठ माना जाता है और हाल ही में यहां रोपवे सहित कई सुविधाओं का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां के मंदिरों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व देश-विदेश में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे उत्तराखंड आकर इन धार्मिक स्थलों के दर्शन करें। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उत्तराखंड में चल रही विकास योजनाओं और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर संतोष जताया। उन्होंने राज्य सरकार को श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों में से एक है और यहां की व्यवस्थाएं बेहतर होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। मुलाकात को चारधाम यात्रा से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हर वर्ष यात्रा शुरू होने से पहले राज्य सरकार केंद्र के साथ समन्वय बढ़ाने और व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर देती है। इस बार भी मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर यात्रा की तैयारियों और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। माना जा रहा है कि इससे चारधाम यात्रा को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। चारधाम यात्रा को उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं, जिससे होटल, परिवहन, स्थानीय व्यापार और अन्य सेवाओं को बड़ा लाभ मिलता है। राज्य सरकार का लक्ष्य इस बार यात्रा को और व्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है। मुख्यमंत्री धामी ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से इस वर्ष की चारधाम यात्रा सफल और सुव्यवस्थित होगी। साथ ही उन्होंने दोहराया कि उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है और सरकार उनकी सुविधा के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

सरकार के 4 वर्षः 'मेरी योजना' पर मंथन

राज्य सरकार के 04 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम कियान्वयन विभाग द्वारा मेरी योजना पुस्तकों, जिसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं का समावेश किया गया है, के संबंध में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह पुस्तकें समस्त जनमानस तक व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु राज्य के सभी जनपदों, विकासखण्डों में वितरित की गई है। सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन ने विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से अवगत कराया और ये बताया कि कैसे सरकार के शासनादेशो 'सरकार जनता के द्वार', 'हमारा संकल्प-अनुशासित प्रदेश' एवं 'हमारा संकल्प-भयमुक्त समाज' के अन्तर्गत जिलों से रोस्टर के आधार पर जिलाधिकारी सहित जिले के समस्त अधिकारी गाँव का भ्रमण कर योजनाओं का निरीक्षण एवं जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करते है, अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण एवं अपराधों की बढ़ोतरी, निस्तारण की भी समीक्षा की जाती है। साथ ही मंडलआयुक्त द्वारा भी निरीक्षण टीम बना कर योजनाओं की समीक्षा की जाती है। उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय मंत्रीगण, सचिव गण एवं विशेष कार्याधिकारियो द्वारा भी भ्रमण कर आख्या दी जाती है। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जारी योजनाओं का एक जगह संकलन कर 'मेरी योजना' पुस्तकों को तैयार किया गया है, जिसमें लगभग सभी विभागों की योजनाओं/सेवाओं का उल्लेख सरल भाषा में करते हुए मुख्यतः इस बिंदु पर फोकस किया गया कि योजना का नाम क्या है, योजना में लाभ क्या मिलता है तथा पात्रता, लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी? और यदि विभाग में आवेदन कर दिया है तो उसके बाद कैसे विभाग उसमें कार्यवाही करता है। ताकि लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल भाषा में स्पष्ट किया जा सके। इन पुस्तकों की प्रिंट प्रतियां समस्त जन प्रतिनिधियों, समस्त विभागाध्यक्षों, राज्य के समस्त राजकीय पुस्तकालयों, समस्त जिलास्तरीय कार्यालयों को इस उददेश्य के साथ भेजी कि योजनाओं की जानकारी ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंच सके। बंशीधर तिवारी, महानिदेशक सूचना ने भी अपने संबोधन में महत्त्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देते हुये शुभकामनायें दी तथा सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक ले जाने की प्रतिबद्धता दिखाई, एस० के० मीणा, उप महानिदेशक आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, साक्षी सिंह, संयुक्त निदेशक अनिल कुमार भारती, कार्यकम प्रमुख दूरदर्शन, आदि अतिथि गणों द्वारा गोष्ठी में प्रतिभाग किया गया तथा राज्य सरकार की समस्त योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सबोधन किया गया। परिचर्चा का संचालन वर्षा सिंह, कार्यक्रम संयोजक द्वारा किया गया। परिचर्चा में भाग लेने वालों में श्री ममगाई जी, प्रोफेसर एवं डीन, दून यूनिवर्सिटी, किरण सूद, फॉर्मर प्रिंसिपल, एम०के० पी, अनूप वाजपेयी, संपादक, अमर उजाला, उत्तराखंड, जनाब सलीम सैफी-न्यूज वायरस नेटवर्क, दिव्य हिमगिरि से कुँवर राज अस्थाना जी ने अपनी उपस्थिति दी। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएसआईआर- भापेसं में 'आगाज 4.0' का आयोजन

सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के एसीएसआईआर साइंस क्लब द्वारा 27 मार्च, 2026 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में "आगाज 4.0" का सफल आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के वैज्ञानिक समुदाय की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का विषय "विज्ञान में महिलाएँ: विकसित भारत की उत्प्रेरक" भारत के वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय एवं नवाचार परिदृश्य को आकार देने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ छात्र समन्वयक द्वारा स्वागत उद्बोधन एवं तत्पश्चात पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। सीएसआईआर-भापेसं के निदेशक, डॉ. हरेंद्र सिंह बिष्ट ने सभा को संबोधित करते हुए भविष्य के निर्माण में वैज्ञानिक नवाचार तथा सहयोगात्मक अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, प्रो. मनोज कुमार धर, निदेशक, एसीएसआईआर की गरिमामयी उपस्थिति ने इस अवसर को और अधिक समृद्ध बनाया। उन्होंने अपने व्याख्यान में, जिसका शीर्षक "भविष्य के शोधकर्ताओं, नवप्रवर्तकों, उद्यमियों एवं राष्ट्रनिर्माताओं का निर्माण" था, में सहयोग की आवश्यकता, बहुविषयक दृष्टिकोण को अपनाने तथा प्रभावी संप्रेषण के लिए स्पष्टता एवं गहरी रूचि के महत्व पर विशेष बल दिया। उन्होंने विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों को एसीएसआईआर द्वारा आई-पीएचडी एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध नए अवसरों की भी जानकारी दी। सत्र का समापन डॉ. हेमंत कुलकर्णी, प्रमुख, एससीडीडी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम में लगभग 200 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की, जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी रचनात्मकता एवं वैज्ञानिक कौशल का प्रदर्शन किया, जिसमें "आत्मनिर्भर भारत"थीम पर रंगोली, "प्रकृति के रूपः प्राकृतिक सौन्दर्य की खोज" विषय पर फोटोग्राफी, तथा "संवहनीय ऊर्जा के विकास की दिशा में भारत की प्रगति" विषय पर ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट शामिल थे। पूरे दिन, शोधार्थियों द्वारा तैयार की गई प्रदर्शनी दीर्घाओं ने आगंतुकों का व्यापक ध्यान आकर्षित किया। भोजनावकाश के उपरांत आयोजित सत्रों में विज्ञान प्रश्नोत्तरी और डम्ब शराड्स जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनके बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित करने हेतु पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह का समापन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं सायंकालीन रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन के साथ हुआ। "आगाज 4.0" ने शोधकर्ताओं, छात्रों और कर्मचारियों को एक साथ आने, विज्ञान का उत्सव मनाने तथा अंतः विषयी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम को इसके सुव्यवस्थित आयोजनएवं सक्रिय सहभागिता के लिए अत्यधिक सराहा गया, जो सीएसआईआर- भापेसं के गत्यात्मक शैक्षणिक वातावरण को दर्शाता है।

दून पुस्तकालय में अनूप साह व एस.एस. रसायली का नागालैण्ड के परिदृश्य पर स्लाइड शो व व्याख्यान

दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की ओर से आज सायं केन्द्र के सभागार में एक बेहतरीन स्लाइड शो का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पद्मश्री से सम्मानित, प्रसिद्ध हिमालयी और वन्यजीव छायाकार अनूप साह, तथा एस. एस. रसाइली, आईएफएस, अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (सेवानिवृत्त) द्वारा नागालैंड की ओर : दीवार पर लगे दर्पण तक की हमारी यात्रा के वृत्तांत शीर्षक से एक स्लाइड शो और व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। इसी विषय पर आधारित एक छाया चित्रों की प्रदर्शनी भी एक दिन पूर्व प्रारम्भ हो गयी है। यह प्रदर्शनी केन्द्र के तीसरे तल पर पांच दिनों तक आम लोगों के दर्शनार्थ प्रातः 11:00-सायं 4:30 बजे तक निशुल्क खुली रहेगी। जिसमें नागालैण्ड के लोगों समाज व संस्कृति के विविध आयामों को दर्शाने का शानदार प्रयास किया गया है। व्याख्यान में बोलते हुए अनूप साह व रसाइली ने कहा कि नागालैण्ड में अपनी विशेष समृद्ध और अनूठी सांस्कृतिक विरासत है. दर्शकों के साथ इस राज्य की यात्रा को हम दृश्य चित्रों व प्राप्त अनुभवों की खुशी और आनंद को साझा कर वार्ता के जरिये यह जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि इस राज्य की संस्कृति और समाज से लोग परिचित हो सकें। इस दौरान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष मेजर जनरल आनंद सिंह रावत (सेवानिवृत्त) ने भी सम्बोधित किया और कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी से एक दूसरे क्षेत्र के समाज, लोगों उनकी बोली भाषा, रहन सहन,खानपान व संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है. उन्होंने नागालैंड में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का नागालैंड में बहुत अधिक सांस्कृतिक महत्व है। जहाँ इसे नागालैंड के राष्ट्रीय पक्षी रूप में महत्व दिया जाता है। यह शक्ति, एकता और नागा पहचान का प्रतीक है, और यह गहराई से जुड़ा हुआ हैऔर नागा लोककथाओं, परंपराओं और मान्यताओं में गहराई से समाया हुआ है। नागालैंड में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसपर भी जानकारी दी गई। बताया गया कि हॉर्नबिल महोत्सव मनाने का विचार मूल रूप से नागालैंड की सौंदर्य एवं आडंबर सोसायटी (BASN) द्वारा शीतकालीन कार्निवल के रूप में प्रस्तावित किया गया था। बाद में इस अवधारणा को नागालैंड सरकार ने अपनाया और दिसंबर 2000 में इसे हॉर्नबिल महोत्सव के रूप में पुनः आरंभ किया। इस महोत्सव को मुख्य रूप से अंतर-जनजातीय संबंधों को मजबूत करने और नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए पुनः शुरू किया जाता है। वर्तमान में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन राज्य पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। यह महोत्सव कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर किसामा गांव में एक निर्धारित क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर देकर कहा कि यहां के समाज को हीन भावना से न देखकर हमें उनकी परिस्थितियों के आधार पर वहां की आजिविका, रहन सहन, खान-पान की जो संस्कृति विकसित हुई उस पर अधिक विचार करने समझने की आवश्यकता समझी जानी चाहिए। व्याख्यान के बाद उपस्थित लोगों ने वक्ता अतिथियों से सवाल -जबाब भी किये. प्रारम्भ में दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र के कार्यक्रम अधिकारी चन्द्रशेखर तिवारी ने लोगों व अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान संस्कृति सचिव उत्तराखण्ड, जुगल किशोर पंत, धनजंय मोहन, बी.एस. रावत, अशोक महर, पंकज नैथानी, डॉ. डी.के. पाण्डे, हरि चंद निमेष, जगदीश बाबला, ज्ञान रंजन, सोहन सिंह रजवार, अंजलि भरतरी, भूमेश भारती, भारत सिंह रावत, भगवान प्रसाद, घिल्डियाल,डॉ डॉ. लालता प्रसाद, जयप्रकाश खंकरियाल, प्रवीन भट्ट, अर्जुन रावत, अम्मार नकवी, शैलेन्द्र नौटियाल, सुंदर सिंह बिष्ट, पूर्व विनोद सकलानी सहित शहर के कई प्रबुद्ध लोग, साहित्यकार, संस्कृतिकर्मी व युवा पाठक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने किया देहरादून-पिथौरागढ़ विमान सेवा का शुभारंभ

एलाइंस एयर देहरादून-पिथौरागढ़ के बीच संचालित करेगा 42 सीटर विमान सेवा

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर देहरादून-पिथौरागढ़-देहरादून विमान सेवा का शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए 42 सीटर विमान सेवा शुरु होने से पिथौरागढ़-देहरादून का सफर एक घंटे में पूरा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह विमान सेवा सामरिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब हवाई यात्रा करना केवल विशिष्ट और सम्पन्न वर्ग के लोगों के लिए ही संभव माना जाता था। परंतु आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हवाई चप्पल पहनने वाला आम नागरिक भी हवाई यात्रा कर सकता है। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2016 में UDAN योजना की शुरुआत कर देश में नागरिक विमानन के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया था। जिसके माध्यम से छोटे शहरों, दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़कर आम नागरिकों को सस्ती दरों पर हवाई सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने दो दिन पूर्व ही उड़ान योजना 2.0 को मंजूरी प्रदान की है। जिसके अंतर्गत, आगामी 10 वर्षों में लगभग 29 हजार करोड़ रुपये के बजट से 100 नए हवाई अड्डों और 200 नए हेलीपैड के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना का विस्तार विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने तथा दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में सस्ती एवं सुगम हवाई सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।

जीवन रेखा बन चुकी है हवाई सेवाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए हवाई सेवाएँ मात्र एक परिवहन का साधन नहीं, बल्कि जीवन रेखा बन चुकी है। दुर्गम और दूरस्थ अंचलों में आवश्यक सामग्री पहुँचाने से लेकर गंभीर रोगियों को त्वरित उपचार के लिए बड़े अस्पतालों तक लाने में हवाई सेवाएं कारगर साबित हो रही हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्तमान में उड़ान योजना के अंतर्गत राज्य में 26 हवाई मार्गों का संचालन किया जा रहा है। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए वर्ष 2023 में "उत्तराखण्ड एयर कनेक्टिविटी योजना" प्रारंभ की गई है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 6 हवाई मार्गों पर उड़ानों का नियमित संचालन किया जा रहा है। बीते चार वर्षों में प्रदेश में हेलिपोर्ट्स की संख्या 2 से बढ़कर 12 हो गई है। साथ ही, हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो चुकी है। उत्तराखंड को "बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम" जैसा राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हो चुका है।

एक घंटे में पूरा होगा पिथौरागढ़ का सफर

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून-पिथौरागढ़ हवाई सेवा के प्रारंभ होने से, पिथौरागढ़ के लोग एक घंटे में देहरादून तक पहुंच सकते हैं। इस सेवा से पिथौरागढ़ की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले हमारे सीमांत क्षेत्रों को वर्षों तक उपेक्षित रखा, जिस कारण इन क्षेत्रों में विकास की गति सीमित रही। आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में काम कर रही हैं। इसी दिशा में चलते हुए पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के बीच भी हेली सेवा प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पिथौरागढ़ हवाई अड्डे को 450 करोड़ रुपये की लागत से विकसित करने का काम भी कर रही है। इसी क्रम में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार के मध्य नैनी सैनी हवाई अड्डे के अधिग्रहण के लिए एमओयू भी किया है, जिससे आने वाले समय में इस क्षेत्र को और भी अधिक फायदा मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापु राममोहन नायडू ने वीडियो संदेश के जरिए देहरादून-पिथौरागढ़ विमान सेवा के लिए अपनी शुभकामानाएं देते हुए राज्य में हवाई सुविधाओं को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया। समारोह में कैबिनेट मंत्री श्री खजान दास, श्री भरत चौधरी, विधायक श्री बृजभूषण गैरोला, पूर्व विधायक श्रीमती चंद्रा पंत, दायित्वधारी श्री हेमराज बिष्ट, एलाइंस एयर के सीएमडी श्री अमित कुमार, उकाडा के सीईओ डॉ. आशीष चौहान, एसीईओ श्री संजय टोलिया मौजूद थे।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्वीकृत किए गए 34 करोड़ के प्रस्ताव

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य आपदा मोचन निधि एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आहूत हुई। बैठक के दौरान जनपदों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि समिति के समक्ष प्रस्तावों को जनपद स्तरीय समिति की सिफारिश पर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जाए। मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग को नदियों की ड्रेजिंग/माइनिंग की एसओपी शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाढ़ सुरक्षा कार्यों से सम्बन्धित प्रस्तावों को सिंचाई विभाग की इस हेतु गतिठ समिति द्वारा टीएसी के उपरान्त राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन नदियों में कटान के कारण प्रत्येक वर्ष कार्य कराना पड़ रहा है, उन्हें चिन्हित कर चौनलाईजेशन की योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि सितारगंज में बैगुल नदी के लिए अध्ययन करा लिया जाए। मुख्य सचिव ने जनपद नैनीताल के चार्टन लॉज को भू-स्खलन से सुरक्षा प्रदान (लागत रू० 699.98 लाख), जनपद पिथौरागढ़ में खोटिला लैंड और घटधार, धारचुला में हिल का ड्रेनेज का कार्य एवं विभिन्न स्थलों पर भू-स्खलन संबंधी कार्य (लागत रू० 3840.78 लाख), जनपद हरिद्वार के मनसा देवी हिल बाईपास रोड का ड्रेनेज और भूस्खलन सम्बन्धित कार्य (लागत रू० 4124.83 लाख), जनपद अल्मोडा के दुधौली बैण्ड से पंचायत घर मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 में एच०पी०बैण्ड पर मार्ग सुरक्षात्मक कार्य (लागत रू० 34.75 लाख), जनपद उत्तरकाषी के धराली झुला पुल का सुरक्षात्मक कार्य (लागत रू० 147.13 लाख), जनपद उत्तरकाषी के नगर पालिका परिशद पुरोला में टैक्सी स्टैण्ड के ऊपर से हो रहे भूस्खलन को रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य (लागत रू० 128.37 लाख), जनपद उत्तरकाषी के हर्षिल मुखवा मोटर मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य (लागत रू० 472.00 लाख), विकास खण्ड सितारगंज में बैगुल नदी के दॉये एवं बॉये पार्श्व में ग्राम रूदपुर के आबादी क्षेत्रों की बाढ़ सुरक्षा कार्य (लागत रू० 146.67 लाख), विकासखण्ड सितारगंज में बैगुल नदी के दांये पार्श्व में ग्राम बीसक्वॉटर के आबादी क्षेत्र की बाढ़ सुरक्षा योजना (लागत रू० 148.48 लाख), तहसील जसपुर में फीका नदी की बाढ़ से ग्राम हजीरों की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य (लागत रू० 419.82 लाख), जनपद नैनीताल में कौशल्यापुरी क्षेत्र की जल भराव की समस्या का समाधान कार्य (लागत रू० 84.77 लाख), रामनगर, नैनीताल के कानियॉ नई बस्ती एवं हिम्मतपुर डोटियाल के आबादी क्षेत्र को बरसाती नाले से जल भराव सुरक्षा कार्य (लागत रू० 112.15 लाख), जनपद देहरूदन के विकासखण्ड रायपुर में डिफेंस कालोनी जोगीवाला एवं बद्रीपुर में बाढ़ सुरक्षा कार्य (लागत रू० 460.45 लाख), जनपद देहरादून के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में दुल्हनी नदी के विभिन्न स्थानों पर यथा, निर्मल कालोनी, बनसरी पुरम, दिल्ली फार्म, लक्ष्मणसिद्ध मंदिर, नकरोंदा रोड (विवेक विहार, वायु विहार) में सुरक्षात्मक कार्य (लागत रू० 412.70 लाख), जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र कैंट के अंतर्गत टोंस नदी के बांये तट पर स्थित स्वर्गाश्रम एवं गोषाला की सुरक्षा दीवार का निर्माण (लागत रू० 186.28 लाख) एवं जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के टौन्स नदी के बांये तट पर स्थित जलवायु टावर की क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य (लागत रू० 88.36 लाख) सहित अन्य विभिन्न कार्यों को स्वीकृति प्रदान की। राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत विभिन्न मदों में अतिरिक्त धनराशि आवंटन हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के सापेक्ष कुल रु० 34.00 करोड की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। इस अवसर पर सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय एवं श्री विनोद कुमार सुमन सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय दंत आयोग में डॉ. हिमांशु ऐरन की एंट्री, 1 अप्रैल से नई पारी की शुरुआत

आर.बी.बी. सुभारती विश्वविद्यालय, देहरादून के पूर्व कुलपति प्रो. डॉ. हिमांशु ऐरन को भारत सरकार के राष्ट्रीय दंत आयोग (National Dental Commission) के असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। वे 1 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। अपनी नियुक्ति पर डॉ. ऐरन ने ईश्वर की कृपा और माता-पिता के आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि सुभारती विश्वविद्यालय, देहरादून में कुलपति एवं प्रति कुलपति के रूप में कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग, स्नेह और समर्थन ने उनके 18 माह के कार्यकाल को अत्यंत यादगार बनाया। उन्होंने सभी सहयोगियों, अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका सहयोग और समर्पण उन्हें निरंतर बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने "राष्ट्र प्रथम-सदैव प्रथम" के संकल्प को दोहराते हुए देश सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। डॉ. ऐरन की इस उपलब्धि पर देहरादून के दंत चिकित्सकों, विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। सभी ने विश्वास जताया कि उनके अनुभव और नेतृत्व से राष्ट्रीय स्तर पर दंत शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिलेगी।

राज्यपाल ने किया 'प्रज्ञानम' एआई चैटबॉट का लोकार्पण

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने बुधवार को लोक भवन में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित 'प्रज्ञानम' एआई चैटबॉट का लोकार्पण किया

'प्रज्ञानमा' एआई चैटबॉट भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह चौटबॉट भारतीय ज्ञान प्रणाली से जुड़े विषयों पर जिज्ञासुओं के प्रश्नों का त्वरित, सटीक एवं संदर्भ आधारित उत्तर प्रदान करने में सक्षम है। इसे विश्वविद्यालय द्वारा 'वन यूनिवर्सिटी-वन रिसर्च' पहल के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा पर किए गए शोध कार्यों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत विषयवस्तु के आधार पर विकसित किया गया है। यह चैटबॉट विशेष रूप से वेद, उपनिषद, पुराण, प्राचीन भारतीय गणित, नाटयशास्त्र, संगीत, आयुर्वेद, दर्शन एवं भारतीय विज्ञान जैसे विषयों पर आधारित विस्तृत डेटाबेस पर निर्मित है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, शोधार्थियों और आम नागरिकों को भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित प्रमाणिक जानकारी डिजिटल माध्यम से सरल एवं त्वरित रूप में उपलब्ध कराना है। यह चैटबॉट https%//pragyanam-live/ पर ऑनलाइन उपलब्ध हो गया है, जहां आम नागरिक, विद्यार्थी एवं शोधार्थी इसे आसानी से उपयोग कर सकते हैं। लोकार्पण कार्यक्रम में राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा वेद, पुराण उपनिषद और प्राचीन सभ्यता में निहित ज्ञान आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि 'प्रज्ञानम' जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस अमूल्य ज्ञान को 21वीं सदी की आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर नई पीढ़ी तक प्रभावी रूप से पहुँचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह चौटबॉट न केवल जिज्ञासाओं का समाधान करेगा, बल्कि शोध आधारित और प्रमाणिक जानकारी प्रदान कर उपयोगकर्ताओं को भारतीय ज्ञान की गहराई से परिचित कराएगा। राज्यपाल ने इस परियोजना के लिए विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह चैटबॉट एक वर्ष के गहन शोध का परिणाम है। इस दौरान भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आधारित महत्वपूर्ण शोध कार्य किए गए तथा दो पुस्तकों का भी निर्माण किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आयोजित कर व्यापक विमर्श किया गया, जिससे इस परियोजना को मजबूत आधार मिला। राज्यपाल ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी तकनीक के साथ अधिक जुड़ी हुई है, ऐसे में 'प्रज्ञानम' उन्हें अपनी जड़ों, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बनेगा। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से इस पहल के 'ब्रांड एंबेसडर' बनने का आह्वान करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड की इस ज्ञान पहल को वैश्विक स्तर तक पहुँचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। लोकार्पण के अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस चैटबॉट के लिए विश्वविद्यालय को बधाई दी और कहा कि देश-विदेश के विद्यार्थी, शोधकर्ता और सामान्य लोग भारतीय ज्ञान परंपरा को डिजिटल माध्यम से आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एन. के. जोशी ने 'प्रज्ञानम' चैटबॉट का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया और इसकी कार्यप्रणाली तथा उपयोगिता के बारे में जानकारी साझा की। लोकार्पण कार्यक्रम को संत समाज तथा शिक्षाविदों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। कार्यक्रम में सचिव राज्यपाल श्री रविनाथ रामन, विधि परामर्शी श्री कौशल किशोर शुक्ल, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. परविंदर कौशल, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रमाकांत पाण्डेय, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अरुण कुमार त्रिपाठी, श्री स्वामी जगन्नाथ आश्रम ऋषिकेश के महंत लोकेश दास जी महाराज,. श्री गरीबदासी आश्रम हरिद्वार के स्वामी रविदेव शास्त्री जी महाराज, चेतन ज्योति आश्रम हरिद्वार के स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी नारायण आश्रम ऋषिकेश के स्वामी नारायण चरण दास महाराज, निर्मल संतपुरा आश्रम हरिद्वार के महंत जगजीत सिंह जी महाराज, कृष्ण कुंज आश्रम ऋषिकेश के स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज, रामनिवास आश्रम हरिद्वार के स्वामी दिनेश दास जी महाराज, स्वामी सुतीक्ष्ण मुनि जी महाराज सहित विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

जनजातीय परंपराओं, ज्ञान और स्थानीय उत्पादों का संरक्षण समय की मांगः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 में किया प्रतिभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज परेड ग्राउंड, देहरादून में राज्य जनजातीय शोध संस्थान, उत्तराखंड द्वारा आयोजित उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर देश के 12 राज्यों से आए जनजातीय वर्ग के प्रतिनिधियों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और परंपराओं के माध्यम से महोत्सव को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने थारू लोक गायिका स्वर्गीय रिंकू देवी राणा एवं श्री दर्शन लाल को 'आदि गौरव सम्मान' से सम्मानित किया। साथ ही, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 14,272.185 लाख रुपये की पेंशन 'वन क्लिक' के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि यह आयोजन केवल एक महोत्सव नहीं, बल्कि जनजातीय समाज की जीवंत विरासत, सादगीपूर्ण जीवन-दर्शन और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि यह मंच जनजातीय भाई-बहनों की पीढ़ियों से संजोई गई लोक परंपराओं और संस्कृति को व्यापक पहचान दिला रहा है तथा राज्य जनजातीय शोध संस्थान को इस भव्य आयोजन के लिए साधुवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज भारतीय संस्कृति की समृद्ध विविधता और प्राचीन परंपराओं का सशक्त आधार है। यह समाज प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीते हुए सतत विकास और सहअस्तित्व का मार्ग दिखाता है तथा सीमांत क्षेत्रों में रहते हुए राष्ट्र की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में आवश्यकता है कि जनजातीय परंपराओं, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय उत्पादों को संरक्षित करते हुए नई पीढ़ी तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, स्वाभिमान और विकास के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सुशासन की पहचान है। इसी सोच के तहत 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय', 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान', 'वन धन योजना' और 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन' जैसी योजनाएं लागू की गई हैं, जिनसे शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर सृजित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय ऐतिहासिक है। साथ ही, देशभर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे नई पीढ़ी प्रेरणा ले सके। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि संथाल समाज की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हैं, जो जनजातीय समाज की बढ़ती भागीदारी का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय कल्याण के बजट में तीन गुना वृद्धि की गई है और सीमांत क्षेत्रों के विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। माणा जैसे दूरस्थ क्षेत्र को 'देश का प्रथम गांव' कहकर नई पहचान दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी इसी दिशा में कार्य करते हुए जनजातीय समाज के जीवन स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रतिवर्ष जनजातीय महोत्सव और जनजातीय खेल महोत्सव के आयोजन का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के 128 जनजातीय गांवों को चिन्हित कर उनके समग्र विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में एकलव्य विद्यालय संचालित हैं, जबकि चकराता और बाजपुर में नए विद्यालय निर्माणाधीन हैं। छात्रवृत्ति, आश्रम पद्धति विद्यालयों और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनजातीय युवाओं के लिए आईटीआई संस्थान, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग, तथा मासिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, चार जनपदों में जनजाति कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति, बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, तथा शोध संस्थान के लिए कॉर्पस फंड की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत बुक्सा और राजी जनजाति क्षेत्रों में बहुउद्देशीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही, पिथौरागढ़ में नए एकलव्य विद्यालय के लिए केंद्र से अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 9 लाख से अधिक लाभार्थियों को मार्च माह की पेंशन के रूप में 142 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी की गई है, जो सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं को यूपीएससी, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु देहरादून में 'आदि लक्ष्य संस्थान' स्थापित किया जा रहा है, जिसमें बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जनजातीय समाज को केवल वोटबैंक के रूप में देखा, जबकि वर्तमान सरकार उनके सम्मान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन प्रेरणादायी है और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर राज्य सरकार सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए कार्य कर रही है। सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है तथा समान नागरिक संहिता लागू करते हुए अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है, ताकि उनकी परंपराएं सुरक्षित रह सकें। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी तथा जनसहभागिता से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री खजान दास, विधायक श्रीमती सविता कपूर, अपर सचिव श्री संजय सिंह टोलिया, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय प्रतिनिधिमंडल तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुनहरा दिनः धामी सरकार की पहल से दूरस्थ क्षेत्रों के लिए नई उम्मीद बनी हेलीकॉप्टर सेवा

जखोली से आसमान तक जीवन की उड़ान, हेलीकॉप्टर सेवा से गर्भवती महिला को समय पर मिला सुरक्षित उपचार

उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आज एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के दिशा-निर्देशों में राज्य सरकार ने दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर आधारित स्वास्थ्य परिवहन सेवा की शुरुआत की है। यह कदम उन इलाकों के लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं है, जहां सड़क और समय दोनों ही बड़ी चुनौती बन जाते हैं। इस पहल ने यह साबित किया है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पहला केस बना मिसाल, समय पर मिला उपचार

इस योजना के तहत 25 मार्च 2026 को पहला सफल मामला सामने आया, जब रुद्रप्रयाग जिले के जखोली क्षेत्र से एक गर्भवती महिला को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग रेफर किया गया। समय रहते महिला को विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उपचार मिला, जिससे उसकी स्थिति को सुरक्षित किया जा सका। यह घटना दर्शाती है कि यदि संसाधनों का सही उपयोग हो तो दुर्गम क्षेत्रों में भी आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी रूप से पहुंचाई जा सकती हैं।

संस्थागत प्रसव को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार की इस पहल का एक बड़ा उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली कई गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पातीं, जिससे जोखिम बढ़ जाता है। हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से अब उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को समय रहते अस्पताल तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आने की संभावना है, जो राज्य के स्वास्थ्य संकेतकों के लिए सकारात्मक संकेत है।

स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन विभाग का समन्वय

इस योजना को सफल बनाने में स्वास्थ्य विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखंड का संयुक्त प्रयास अहम भूमिका निभा रहा है। दोनों विभागों के बीच बेहतर समन्वय से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जरूरतमंद मरीजों को समय पर हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध हो सके। यह पहल सरकार की बेहतर प्रशासनिक कार्यशैली और विभागीय तालमेल का उदाहरण भी प्रस्तुत करती है।

सरकार की संवेदनशील और दूरदर्शी कार्यशैली

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार ऐसी योजनाएं लागू कर रही है, जो सीधे आम जनता को राहत पहुंचाती हैं। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत इस बात का प्रमाण है कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे का बयान

स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के दिशा-निर्देशों में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ और समावेशी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करना इसी सोच का परिणाम है, ताकि किसी भी महिला को समय पर उपचार से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि यह पहल विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसे मामलों में समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक होता है। सरकार का प्रयास है कि राज्य के हर नागरिक को, चाहे वह किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो, समान रूप से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने यह भी कहा कि आने वाले समय में इस सेवा का विस्तार किया जाएगा और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर सुधार किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया आपको सफलता दिलाएगा। बच्चों के परिणाम से संतुष्टि मिलेगी। घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी। अतिथि सत्कार में भी समय बीतेगा। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलेगी। जोखिम भरे कामों से दूर रहें और वाहन भी सावधानी से चलाएं। गिरने या चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 7

वृषभ राशि- प्रॉपर्टी या वाहन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा कोई काम चल रहा है, तो आज उससे जुड़ी कोई बात आपके पक्ष में हो सकती है। संतान की तरफ से सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और सकारात्मकता बढ़ेगी। नौकरीपेशा लोग समय पर अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 3

मिथुन राशि- किसी खास मित्र के साथ विचार-विमर्श होगा। मन में चल रहा कोई पुराना द्वंद्व खत्म हो सकता है। मीडिया और ऑनलाइन गतिविधियों से नई जानकारी मिलेगी। रिश्तेदारों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। कोई भी यात्रा आज टालना ही बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप से जुड़ी कोई योजना भी बन सकती है। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। भाग्यशाली रंग- गुलाबी, भाग्यशाली अंक- 5

कर्क राशि- परिवार के लोगों में उत्साह बना रहेगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले बजट बना लें, इससे आर्थिक दिक्कत से बचेंगे। बातचीत के दौरान आपके मुंह से ऐसी बात निकल सकती है, जो रिश्तों के लिए नुकसानदायक हो। लव पार्टनर से मुलाकात का मौका मिलेगा। तनाव का असर आपकी पाचन क्रिया पर पड़ सकता है। भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 2

सिंह राशि- भूमि और वाहन खरीदने के अच्छे योग बन रहे हैं। आपका वैज्ञानिक नजरिया और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। कोई विवादित मामला भी आज सुलझ सकता है। रुपए-पैसे के मामलों में किसी पर ज्यादा भरोसा न करें। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। कमर और पेट में दर्द बढ़ने से दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 5

कन्या राशि- सोचे हुए काम पूरे होने से उत्साह बना रहेगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा और परिजनों से मुलाकात होगी। व्यवसाय करने वालों के लिए आज कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन मेहनत के अनुसार उचित परिणाम भी मिलेंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। सावधान रहें और उचित आराम लें। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 2

तुला राशि- करीबी लोगों का विश्वास और सहयोग मिलेगा। उनका मार्गदर्शन आपके लिए महत्वपूर्ण रास्ता खोल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। बच्चों के विवाह से जुड़ी योजनाएं भी बन सकती हैं। परिवार के लोगों के साथ विचारों का आदान-प्रदान सकारात्मकता देगा। खांसी, जुखाम जैसे इंफेक्शन से बचाव रखें। भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 4

वृश्चिक राशि- भागदौड़ की बजाय शांत और सकारात्मक तरीके से काम करें। इससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर रहेंगे। युवाओं को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग अपने प्रोजेक्ट पर ज्यादा फोकस रखें। प्रेम संबंध ों में भी मर्यादा बनी रहेगी। योग और व्यायाम पर ज्यादा ध्यान दें। भाग्यशाली रंग- ऑरेंज, भाग्यशाली अंक- 6

धनु राशि- समय का सही प्रबंधन करना जरूरी है। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात बहुत लाभदायक रहेगी। युवा मौज-मस्ती की वजह से अपने जरूरी कामों में लापरवाही कर सकते हैं, नुकसान हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को काम की अधिकता से तनाव रहेगा, लेकिन चिंता न करें, प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 7

मकर राशि- दूसरों के मामलों में दखल न दें, वरना लोगों के बीच आपकी छवि खराब हो सकती है। हालात को मजबूत करने के लिए किसी गलत तरीके का सहारा न लें। सहज ढंग से अपने काम पूरे करते जाएं। पति-पत्नी के बीच मधुर तालमेल रहेगा। नजला-जुखाम जैसी परेशानी रह सकती है। आयुर्वेदिक तरीका फायदेमंद रहेगा। भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 5

कुंभ राशि- समय मिला-जुला प्रभाव देने वाला रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दें। घकिसी संबंधी के यहां जाने का निमंत्रण भी मिल सकता है। बहुत व्यस्तता के बावजूद बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देना जरूरी है। उनके साथ भी थोड़ा समय जरूर बिताएं। लेनदेन के मामलों में बिल्कुल लापरवाही न करें। भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 1

मीन राशि- महिलाएं अपने काम बहुत आत्मविश्वास और लगन से पूरा कर पाएंगी। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर आलोचना भी करेंगे, लेकिन उसका नकारात्मक असर अपने ऊपर न आने दें। अपने काम पर फोकस रखें। ज्यादा काम और तनाव की वजह से घबराहट और थकान महसूस हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग- हल्का नीला, भाग्यशाली अंक- 8

EXPERIENCE HELI TOUR WITH

Himgiri Aviation & Tourism

SINCE 2018

3N/4D TOUR

A Unit of दिव्य हिमगिरि

केदार-बद्री यात्रा

BY HELICOPTOR

OPENING DATES

KEDARNATH	BADRINATH
22 April, 2026	23 April, 2026

ADVANCE BOOKING STARTS BOOK NOW

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

Contact for Reservation 8433456398, 9410353164

Email: himgiritourism@gmail.com

6 Municipal Road, Opp. Oxford School of Excellence, Dalanwala, Dehradun-248001 (UK)